vishikhamedia@gmail.com
विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI No. RAJHIN/2019/77486

_vishikhamedia/ vishikhamedia/

तीर निशाने पर

विशिखा

मूल्यः 25 रूपये

वर्ष:07 अंक:4 अप्रैल 2025 पृष्ठ:32

vishikhamedia vishikhamedia.in

राजस्थान संस्करण

योगी सरकार के आठ साल

वाह से आह तक

यूपी में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकार्ड भी योगी के नाम हो गया है।

विशिखा

न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

मिशन-2027 की तैयारी बीजेपी यूपी में नया चेहरा लाने की तैयारी

2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों में आई कमी ने पार्टी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर राज्य में जनाधार कैसे मजबूत किया जाए और 2027 में सत्ता की हैट्रिक कैसे बनाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।

10

05 यूपीआई से लेनदेन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

06 प्रत्येक दोपहिया वाहन के साथ दो आईएसआई प्रमाणित हेलमेट रखना जरूरी- नितिन गडकरी

10 बिहार में बाबाओं के प्रवचन या चुनावी प्रचार क्या है असल मकसद

14 सेना कर्मियों के बीमा कवर में बढ़ोतरी, एसबीआई के साथ एमओयू साइन

16 पार्किंसन तेज गति से बढ़ रही है ये बीमारी, नहीं है इसका कोई भी इलाज

18 रोप-वे से अब चंद मिनटों में पहुंच सकेंगें केदारनाथ धाम

20 अमेरिका में बंद होगा शिक्षा मंत्रालय, ट्रंप ने लिया फैसला

22 दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आवास पर लगी आग में मिली भारी मात्र में नगदी

24 संकट में पाकिस्तान अंदर-बाहर हर तरफ हाहाकार

28 पंजाब में किसान आंदोलन पर कड़ा एक्शन, आप सरकार ने बदला रुख

विशिखा
तीर निशाने पर
अंक: 4 वर्ष:07, अप्रैल 2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

विशिखा
तीर निशाने पर

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** 191/56 (जानकी देवी स्कूल के पास) सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर- 302033 राजस्थान के लिए प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका मे प्रकाशित सामग्री के विषय मे अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व-लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका मे प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
*किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
*पत्रिका मे प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़ो को इन्टरनेट एवं अन्य वेवसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात. आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

लोकतंत्र का एक सबसे मजबूत स्तम्भ कहे जाने वाले न्यायपालिका के एक न्यायाधीश के घर होली पर लगी आग ने कितने ही अरमानों को जलाकर रख कर दिया, उच्च न्यायालय में बैठे एक न्यायमूर्ति के घर पर लगी आग ने पूरे देश को झकझोर दिया, किसी ने सोचा नहीं था कि जिसके पास हम बड़े ही विश्वास के साथ न्याय के लिए जाते हैं, वहीं पर उसे ये सब देखने को मिलेगा....

अग्निशमन दल के एक उच्च अधिकारी ने तो ऐसी किसी भी घटना होने से साफ इंकार कर दिया था, पर धन्य है वह कर्मचारी जिसने घटना के वक्त अधजले नोटों का वीडियो बना लिया, वर्ना ये राज भी उसी वक्त नोटों के साथ जलकर राख हो जाता. आज याद आता है वर्ष 2017 का वह दिन जब एक अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार में लिप्त कई न्यायमूर्तियों पर एक पत्र लिखकर आगाह किया था इसका उन्हें खामियाजा भी उठाना पड़ा था, पर शायद उस वक्त न्यायपालिका और कार्यपालिका में बैठे लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ. पर शायद इस बार होली की आग ने भ्रष्टाचार को जलाकर उसका दूसरा पक्ष सामने रख दिया... अब देखना यह है कि न्यायपालिका इस देश और माननीय न्यायमूर्ति के साथ कितना न्याय करती है...

शेष फिर

यूपीआई से लेनदेन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

सरकार ने योजना को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यूपीआई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है, जिससे यूपीआई से भुगतान प्राप्त करने पर कमाई का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को स्वीकृति दी है, जिससे छोटे दुकानदारों को विशेष लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत यूपीआई से पेमेंट स्वीकार करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। मोदी सरकार इस योजना पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार के अनुसार, यह पेमेंट प्रणाली दुकानदारों के लिए सरल, सुरक्षित और तेज होगी, जिसमें धन सीधे बैंक खाते में आएगा, वह भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।

1 अप्रैल से शुरू होगी योजना

केंद्र सरकार की यह प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागू होगी, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगी। इस योजना के तहत, 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन करने वालों को लाभ मिलेगा, जिससे विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को

फायदा होगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर प्रति ट्रांजैक्शन 0.15 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही, सभी श्रेणियों के लेनदेन के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होगा, जिससे डिजिटल लेनदेन पूरी तरह से लागत–मुक्त रहेगा।

बैंकों को भी मिलेगा प्रोत्साहन

यदि कोई ग्राहक 1,000 रुपये की खरीदारी करता है और यूपीआई से भुगतान करता है, तो दुकानदार को 1.5 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत बैंकों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार बैंकों द्वारा किए गए दावों की 80 प्रतिशत राशि तुरंत जारी करेगी, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि तभी मिलेगी जब बैंक की तकनीकी खराबी 0.75 प्रतिशत से कम होगी और उनका सिस्टम अपटाइम 99.5 प्रतिशत से अधिक रहेगा।

सरकार ने रखा बड़ा लक्ष्य

केंद्र सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024–25 में 20,000 करोड़ रुपये के यूपीआई लेनदेन को पूरा करना है। यह योजना पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने और छोटे शहरों व गांवों तक यूपीआई को लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, सरकार यूपीआई सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने और तकनीकी खराबियों को कम करने पर भी ध्यान दे रही है। योजना के तहत, छोटे व्यापारियों को यूपीआई से पेमेंट स्वीकार करने के लिए अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा।

योगी सरकार के आठ साल
वाह से आह तक

यूपी में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकार्ड भी योगी के नाम हो गया है।

योगी सरकार की बुलडोजर नीति को एक तरफ सख्त कार्रवाई का उदाहरण बताया जाता है, लेकिन विपक्ष इसे पक्षपातपूर्ण और गरीबों के खिलाफ करार देता है। कई मामलों में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए ही घरों और दुकानों को ढहा दिया गया, जिससे विवाद हुआ।

मुख्यमंत्री आवास योजना के हर उस लाभार्थी को आवासीय पट्टा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया गया है, जिनके पास भूमि नहीं थी। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। यही तो है अंत्योदय।

अजय कुमार,लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं, जबकि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना आठ साल पूरा कर चुके हैं। यूपी में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकार्ड भी योगी के नाम हो गया है। करीब 24 करोड़ आबादी को यदि योगी से पूर्व की सरकारों के तौरतरीकों की याद होगी तो वह जानते होंगे कि आठ साल पहले प्रदेश का क्या हाल था। यूपी की गणना बीमारू राज्य के रूप में होती थी। साम्प्रदायिक हिंसा, संगठित अपराध, दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा अखिलेश सरकार की पहचान थी। आतंकवादियों के मुकदमें वापस लिये जाते थे। तुष्टिकरण समाजवादी सरकार की पहचान बन गई थी। दंगा पीड़ितों को उनका धर्म देखकर मुआवजा बांटने

का कारनामा भी अखिलेश सरकार द्वारा किया गया था। सपा के नेता थानों तक में गुंडागर्दी करने से घबराते नहीं थे। आजम खान जैसे समाजवादी नेताओं की बदजुबानी के किस्से आम थे। हिन्दू देवी देवताओं का अपमान समाजवादी सरकार की आदत बन गई थी। हाल यह है कि आठ साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी अखिलेश की राजनीति नहीं बदली है। विकास के नाम पर अखिलेश एक्सप्रेस वे और लखनऊ में मेट्रो के अलावा कुछ नहीं गिना पाते थे।

एक वह दौर था जब प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी तो अब फाइलों में विकास नहीं उलझता है, बल्कि जमीन पर फलफूल रहा है। अपराधी ठोके जा रहे हैं। भू माफियाओं से कब्जाई जमीन वापस ली जा रही है। संगठित अपराध करने वालों को चुन चुनकर मिटाया जा रहा है। मगर पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के प्रति धारणा बदलने में सफलता प्राप्त की है। कभी बीमारू राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज व्यवसाय एवं निवेश का सर्वश्रेष्ठ ठिकाना बनकर देश और दुनिया में पहचाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज 'ग्रोथ गियर' है। हमें विरासत में अराजकता, अव्यवस्था और अपराध के अंधकार में डूबा हुआ प्रदेश मिला था। ऐसे राज्य को सुरक्षित परिवेश, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुगम कनेक्टिविटी और उद्यम अनुकूल नीतियों द्वारा निवेशकों

योगी राज में तमाम अच्छे कार्य हो रहे हैं तो कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश की सत्ता योगी तक केन्द्रित हो कर रह गई है। बीजेपी तक के सांसदों और विधायकों की नहीं सुनी जाती है। योगी का सख्त आदेश है कि कोई विधायक सिफारिश लेकर किसी अधिकारी या थाना-चौकी पर नहीं जायेगा, परिणाम स्वरूप ब्यूरोक्रेसी और पुलिस निरंकुश हो गई है।

का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाने में हम लोग सफल रहे। विगत आठ वर्षों में प्रदेश को प्राप्त हुए 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव इसकी पुष्टि करते हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इनके माध्यम से 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों हेतु रोजगार का सृजन हुआ है। स्थापित सत्य है कि सुरक्षा के सुपथ पर ही विकास कुलांचे भरता है और सुगम कनेक्टिविटी उसे तीव्रता प्रदान करती है। 'नया उत्तर प्रदेश' उसका जीवंत उदाहरण है।

महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास ही अंत्योदय है। प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार की हर योजना में यह भाव श्वास लेता है। यही कारण है कि बीते आठ वर्षों में प्रदेश सरकार ने छह करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धनों को प्रतिमाह निःशुल्क अनाज, 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.21 करोड़ लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा सुरक्षा कवच, 56.50 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क आवास जैसे अनेक कल्याणकारी उपहारों ने प्रदेश के करोड़ों नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। सभी को आवास के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के हर उस लाभार्थी को आवासीय पट्टा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया गया है, जिनके पास भूमि नहीं थी। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। यही तो है अंत्योदय।

आजादी से लेकर 2017 तक प्रदेश में 12 मेडिकल कालेज थे। आज राज्य में 44 राजकीय मेडिकल कालेज और 36 निजी मेडिकल कालेजों सहित 80 मेडिकल कालेज संचालित हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का संचालन आरंभ हो गया है। 'एक जनपद–एक मेडिकल कालेज' की संकल्पना उत्तर प्रदेश में साकार हो रही है। प्रदेश में 122 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। मार्च, 2017 से अब तक तीन नई चीनी मिलों की स्थापना

हुआ है, जिससे लगभग 1.25 लाख लोगों को प्रत्यक्षध्अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। आठ वर्षों में 46.50 लाख गन्ना किसानों को 2,80,223 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, पीएम स्वनिधि योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं मातृशक्ति के जीवन में सकारात्मकता का सवेरा लेकर आई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की 95 लाख से अधिक महिलाओं को ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ने के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 2,510 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन, ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) घर की महिला के नाम आदि जैसी रचनात्मक पहल नारी शक्ति के जीवन में सम्मान और आर्थिक प्रगति का प्रतीक हैं।

प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का युगांतरकारी कार्य किया है। वर्ष 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत थी जो अब तीन प्रतिशत है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये विभिन्न आयोगों एवं भर्ती बोर्ड द्वारा साढ़े आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली।

इनमें से 1.38 लाख से अधिक महिलाएं हैं। परीक्षाओं के शुचितापूर्ण आयोजन के लिए उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) कानून लागू किया गया है, जिससे छात्रों के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास जागा है। आठ वर्ष हमारी आस्था, अस्मिता, आर्थिकी और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन का ऐतिहासिक कालखंड है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते आठ वर्षों में प्रदेश में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में डीजल–पेट्रोल दरें देश में सबसे कम हैं। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में समृद्धि के नए सोपान चढ़ रहा है। इस सफलता के पीछे रामराज्य की अवधारणा ही है।

खैर योगी राज में तमाम अच्छे कार्य हो रहे हैं तो कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश की सत्ता योगी तक केन्द्रित हो कर रह गई है। बीजेपी तक के सांसदों और विधायकों की नहीं सुनी जाती है। योगी का सख्त आदेश है कि कोई विधायक सिफारिश लेकर किसी अधिकारी या थाना–चौकी पर नहीं जायेगा, परिणाम स्वरूप ब्यूरोक्रेसी और पुलिस निरंकुश हो गई है। योगी सरकार ने निवेश आकर्षित करने और नए उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में कई कदम उठाए, लेकिन बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है। सरकारी भर्तियों में देरी, पेपर लीक की घटनाएं और युवाओं को अपेक्षित संख्या में नौकरियां न मिलना एक बड़ी चुनौती रही है। वहीं योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के दावे काफी किए, लेकिन कई विभागों में रिश्वतखोरी और सरकारी अधिकारियों की मनमानी की शिकायतें बनी हुई हैं। खासकर तहसील, थाने और नगर निकायों में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।

पेट्रोल–डीजल, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीजों की महंगाई बढ़ी है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न मिलने, फसलों के उचित दाम न मिलने और बिजली की बढ़ती दरों से किसान परेशान रहे हैं। सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई के लिए 'ठोक दो' नीति अपनाई, लेकिन पुलिस की मनमानी, फर्जी एनकाउंटर और निर्दोष लोगों पर अत्याचार के आरोप भी लगे। थानों में दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सुनवाई न होने की शिकायतें अक्सर आती रही हैं।

योगी सरकार की बुलडोजर नीति को एक तरफ सख्त कार्रवाई का उदाहरण बताया जाता है, लेकिन विपक्ष इसे पक्षपातपूर्ण और गरीबों के खिलाफ करार देता है। कई मामलों में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए ही घरों और दुकानों को ढहा दिया गया, जिससे विवाद हुआ। उधर, कई सरकारी योजनाओं की घोषणाएं हुईं, लेकिन उनका लाभ सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाया। पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना और स्वरोजगार योजनाओं में भ्रष्टाचार और भेदभाव की काफी शिकायतें सामने आईं हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार की वाह–वाह भी खूब हो रही है, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि योगी राज में जनता कराह रही है। उसकी आह को कोई सुनने वाला नहीं है।

प्रत्येक दोपहिया वाहन के साथ दो आईएसआई प्रमाणित हेलमेट रखना जरूरी- नितिन गडकरी

भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। हर साल 4,80,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1,88,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इन मृतकों में से 66 प्रतिशत लोग 18 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं। खासकर दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसों में हर साल 69,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत मौतें हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती हैं। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्ताव रखा है कि सभी दोपहिया वाहनों की बिक्री के साथ दो आईएसआई प्रमाणित हेलमेट अनिवार्य रूप से दिए जाएं। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की गई, जिसे टू–व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूरा समर्थन मिला है।

उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

टू–व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन लंबे समय से आईएसआई प्रमाणित हेलमेट की अनिवार्यता की मांग कर रहा था। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने नितिन गडकरी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, ष्यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता है। हेलमेट जीवन की सुरक्षा करते हैं, और हर बाइक खरीद के साथ इन्हें अनिवार्य बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है सड़क दुर्घटनाओं में

अपनों को खोया है। उद्योग जगत ने यह भी कहा कि दोपहिया वाहनों की सवारी को सुरक्षित बनाना अब प्राथमिकता होनी चाहिए। राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के पास आईएसआई प्रमाणित हेलमेट होने से यात्रा सुरक्षित और जिम्मेदारी भरी बनेगी।

हेलमेट निर्माता संघ का आश्वासन

हेलमेट निर्माता संघ ने आश्वासन दिया है कि वे गुणवत्तापूर्ण आईएसआई हेलमेट के उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे और देशभर में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने इस पहल को सड़क सुरक्षा में एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह कदम भारत में सुरक्षित और समझदारी भरी दोपहिया यात्रा के नए युग की शुरुआत करेगा, क्योंकि हर हेलमेट के पीछे एक कीमती जीवन होता है।

आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट क्या हैं?

आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट वे हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। इन हेलमेट्स पर आईएसआई का निशान होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हेलमेट ने कड़े गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षणों को पास किया है।

हेलमेट पर आईएसआई मार्क क्यों जरूरी

आईएसआई मार्क यह सुनिश्चित करता है कि हेलमेट सरकार द्वारा स्वीकृत सुरक्षा मानकों के अनुसार बना है। बिना आईएसआई प्रमाणपत्र वाले हेलमेट पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते, जिससे दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है।

आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट की पहचान

- हेलमेट पर स्पष्ट रूप से आईएसआई मार्क होना चाहिए।
- मार्क के नीचे 7 अंकों का लाइसेंस नंबर होना चाहिए।
- "IS 4151:2015" कोड होना चाहिए, जो दोपहिया वाहनों के लिए मान्य हेलमेट का मानक है।

कानूनी अनिवार्यता

भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत आईएसआई प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना प्रमाणित हेलमेट के पकड़े जाने पर चालान काटा जा सकता है। यह प्रमाणपत्र हेलमेट की मजबूती, झटकों को सहने की क्षमता और गुणवत्ता की गारंटी देता है, जिससे यह एक सुरक्षित विकल्प बनता है।

मिशन-2027 की तैयारी बीजेपी यूपी में नया चेहरा लाने की तैयारी

2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों में आई कमी ने पार्टी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर राज्य में जनाधार कैसे मजबूत किया जाए और 2027 में सत्ता की हैट्रिक कैसे बनाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।

अजय कुमार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही दो साल बाद होने वाले हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों में आई कमी ने पार्टी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर राज्य में जनाधार कैसे मजबूत किया जाए और 2027 में सत्ता की हैट्रिक कैसे बनाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। हाल ही में 70 जिला और महानगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर मंथन शुरू हो चुका है। पार्टी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है, जो न केवल संगठन को मजबूत कर सके, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की राह भी आसान बना सके।

बीजेपी के संविधान के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तब किया जा सकता है जब 50 प्रतिशत से अधिक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी हो। इस बार 71 प्रतिशत से अधिक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जिससे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाया गया है और वे जल्द ही लखनऊ का दौरा कर सकते हैं। पार्टी का पूरा ध्यान ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर है, जो पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सके।

उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर को देखें तो बीजेपी ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं की अगुवाई में लड़े थे। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य और 2022 में स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और दोनों चुनावों में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार भी पार्टी किसी ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। यह इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) गठजोड़ के सहारे बीजेपी को तगड़ी

चुनौती दी थी और कई सीटों पर बढ़त हासिल की थी।

उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण का राजनीति पर गहरा असर पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं और पूर्वांचल में उनकी गहरी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य जातीय समूह के नेता को सामने लाकर संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। चर्चा में आए संभावित नामों में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा, जल–शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शामिल हैं। इनमें से धर्मपाल सिंह और बी एल वर्मा ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि दिनेश शर्मा ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चयन सिर्फ जातीय समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठनात्मक कुशलता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए विपक्ष के मजबूत गठबंधन से मुकाबला करना होगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राज्य में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है, जो चुनावी रणनीति को सही दिशा में ले जा सके और पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सके। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐसा चेहरा तलाशा जा रहा है, जो सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाए रख सके। पिछले कुछ वर्षों में संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। डिप्टी

प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद बीजेपी पूरी तरह से मिशन–2027 में जुट जाएगी। पार्टी का मुख्य लक्ष्य अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने के साथ ही नए वोटरों को भी जोड़ना होगा। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा।

सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कई बार यह बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं के बीच यह धारणा बनी थी कि योगी सरकार में उनकी सुनवाई कम हो रही है और नौकरशाही का दखल बढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत है, जो न केवल संगठन को मजबूत करे, बल्कि सरकार और संगठन के बीच किसी भी तरह के टकराव को भी रोके।

प्रदेश अध्यक्ष के चयन में दिल्ली और लखनऊ के बीच संतुलन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो, जो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों को समझे और उन पर अमल करे, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी अच्छे तालमेल के साथ काम करे। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनका योगी सरकार के साथ अच्छा तालमेल था। भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल में संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को लेकर कई बार सवाल उठे। इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे नेता की तलाश की जा रही है, जो सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठा सके और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सके।

रणनीति कारों का मानना है कि 2027 के चुनाव में पार्टी को नए तरीके से रणनीति बनानी होगी। 2017 और 2022 में पार्टी ने विकास और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को झटका लगा क्योंकि विपक्ष ने जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में कर लिया था। ऐसे में 2027 के चुनाव में बीजेपी को सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वही चुनावी रणनीति को जमीन पर लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष का एक और महत्वपूर्ण दायित्व उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को सुचारू बनाना होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर अक्सर असंतोष देखने को मिलता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर गलत उम्मीदवारों के चयन की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी को ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, जो न केवल मजबूत संगठनकर्ता हो, बल्कि टिकट बंटवारे में भी निष्पक्षता और संतुलन बनाए रख सके।

प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद बीजेपी पूरी तरह से मिशन–2027 में जुट जाएगी। पार्टी का मुख्य लक्ष्य अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने के साथ ही नए वोटरों को भी जोड़ना होगा। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा। बीजेपी की कोशिश है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो, जो पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी को चुनावी मोड में ला सके और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए प्रेरित कर सके। बीजेपी के भीतर इस मुद्दे पर गहन मंथन चल रहा है और जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस चेहरे पर दांव लगाती है और वह चेहरा पार्टी को 2027 में सत्ता की हैट्रिक दिलाने में कितना सफल होता है।

बिहार में बाबाओं के प्रवचन या चुनावी प्रचार क्या है असल मकसद

बिहार हमेशा से जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, आर्ट अश्वफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की हर संभव कोशिश कर रही है।

अजय कुमार, लखनऊ

बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे–जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे–वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। हर दल अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार करने में जुटा है, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में सिर्फ राजनीतिक चेहरे ही नहीं, बल्कि धार्मिक गुरु भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु, प्रवचन कर्ता और संत बिहार का दौरा कर रहे हैं, और इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार हमेशा से जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की हर संभव कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है क्योंकि अभी तक वह राज्य में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। हर बार उसे किसी सहयोगी दल की जरूरत पड़ी है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार का दौरा कर चुके हैं, जिससे सियासी माहौल पहले ही गर्म हो चुका था और अब धार्मिक गुरुओं की एंट्री ने इसे और गरमा दिया है।

बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के प्रभाव वाले इलाके गोपालगंज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का

पहुंचना महज संयोग नहीं कहा जा सकता। धीरेंद्र शास्त्री यहां पांच दिनों तक हनुमंत कथा कर रहे हैं, और उनकी कथाओं में हिंदुत्व का एजेंडा साफ झलक रहा है। उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं बल्कि हिंदुओं को जागरूक करने के लिए यहां पहुंचे हैं। हालांकि, उनके इस बयान को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हिंदुत्व के नाम पर भीड़ जुटाने की उनकी कला और बीजेपी नेताओं से उनकी करीबी किसी से छिपी नहीं है। गोपालगंज, जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वहां जाकर हिंदुत्व पर जोर देना साफ तौर पर बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। यह रणनीति खासतौर पर बिहार में जातीय राजनीति के मुकाबले धार्मिक ध्रुवीकरण को मजबूत करने की कोशिश लगती है। यह पहला मौका नहीं है जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस तरह के बयान दिए हैं, बल्कि वे लगातार हिंदू एकता की बात करते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को अगर छेड़ा गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे, और यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में चुनावी बिसात बिछ रही है।

धीरेंद्र शास्त्री के बिहार दौरे के ठीक बाद आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी बिहार पहुंच गए। उनका भी बिहार दौरा महज आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। श्री श्री रविशंकर ने पटना के गांधी मैदान में सत्संग का आयोजन किया, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने ध्यान, योग और जीवन जीने की कला पर प्रवचन दिए, लेकिन उनके दौरे की सबसे अहम बात वह 1000 साल पुराना पवित्र शिवलिंग था, जिसे वे बिहार लेकर आए थे। यह वही शिवलिंग है जिसे 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खंडित कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि सदियों से एक अग्निहोत्री परिवार इस शिवलिंग को संभालकर रखे हुए था, और अब इसे सार्वजनिक दर्शन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को जगाने और

बिहार चुनाव से पहले धार्मिक बाबाओं का यह दौरा महज संयोग नहीं, बल्कि एक सियासी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी यह समझ चुकी है कि बिहार में जातीय समीकरणों के चलते उसे सत्ता पाने में दिक्कत होती रही है, इसलिए अब वह हिंदुत्व को केंद्र में रखकर चुनावी लड़ाई लड़ना चाहती है। यह रणनीति कितनी सफल होगी,

उन्हें एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। श्री श्री रविशंकर का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। यही कारण है कि उनके बिहार पहुंचने के तुरंत बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनसे मिले और बिहार सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बिहार में हैं। उनका पांच दिवसीय दौरा जारी है, और इस दौरान वे संघ के स्वयंसेवकों और बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। भागवत ने अपने इस दौरे में बिहार के लोगों की तारीफ की और कहा कि वे समर्पण, कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उन्होंने दशरथ मांझी का उदाहरण देते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करके सफलता पाई जा सकती है। हालांकि, उनके इस दौरे को सिर्फ आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। संघ प्रमुख का बिहार आना, वह भी चुनाव से पहले, यह बताने के लिए काफी है कि बीजेपी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। बीजेपी के लिए बिहार चुनाव हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि राज्य में जातीय समीकरण काफी मजबूत हैं। अब तक बीजेपी को जेडीयू के सहारे ही सत्ता में हिस्सेदारी मिलती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेल रही है।

धार्मिक गुरुओं का बिहार में एक के बाद एक पहुंचना और उनके प्रवचनों में हिंदुत्व की बातें करना यह साबित करता है कि बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है। आरजेडी ने साफ कहा है कि बीजेपी यह सब चुनावी फायदे के लिए कर रही है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी धार्मिक गुरुओं को आगे कर बिहार में एक नई राजनीतिक धारा बहाना चाहती है। हालांकि, बीजेपी इस तरह के आरोपों को नकारती रही है, लेकिन यह तो साफ है कि इन सभी घटनाओं का एक खास मकसद है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन बीजेपी अब इसे हिंदुत्व के आधार पर बदलने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में इसे मजबूती से लागू करने की कोशिश पहली बार इतनी खुलकर हो रही है। संघ भी लगातार इस रणनीति पर काम कर रहा है कि जातियों में बंटे हिंदुओं को एक मंच पर लाया जाए, ताकि इसका चुनावी फायदा बीजेपी को मिले।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहले भी हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी हिंदू जागरण के लिए यात्रा निकाली थी, और अब बिहार में भी उनका यही उद्देश्य नजर आ रहा है। श्री श्री रविशंकर के महमूद गजनवी द्वारा खंडित शिवलिंग को लेकर बिहार आने का भी यही मकसद हो सकता है कि हिंदुओं की भावनाएं जाग्रत हों और वे एकजुट होकर एक खास विचारधारा के समर्थन में खड़े हों। सब घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो यह साफ होता है कि बिहार चुनाव से पहले धार्मिक बाबाओं का यह दौरा महज संयोग नहीं, बल्कि एक सियासी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी यह समझ चुकी है कि बिहार में जातीय समीकरणों के चलते उसे सत्ता पाने में दिक्कत होती रही है, इसलिए अब वह हिंदुत्व को केंद्र में रखकर चुनावी लड़ाई लड़ना चाहती है। यह रणनीति कितनी सफल होगी, यह तो चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार में इस बार का चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों

सेना कर्मियों के बीमा कवर में बढ़ोतरी, एसबीआई के साथ एमओयू साइन

भारतीय सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ में सेवारत कर्मियों के श्पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंसश कवर को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। हवाई दुर्घटना बीमा कवर (एएआई) की राशि अब बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दी गई है। एसबीआई ने इन बलों के कर्मियों के लिए बीमा कवर की राशि में वृद्धि की है। डिफेंस सैलरी पैकेजध्केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज के संबंध में भारतीय सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ ने एसबीआई के साथ एक समझौता (एमओयू) किया था। यह एमओयू भारतीय सेना के लिए 16 जनवरी, वायुसेना के लिए 17 जनवरी और सीआरपीएफ के लिए 31 जनवरी को साइन किया गया था।

सेवारत कर्मियों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (पीएआई) की राशि को दोगुना कर दिया गया है। भारतीय सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ के पेंशनभोगियों के लिए भी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई) की राशि बढ़ाई गई है। पहले सीआरपीएफ के कर्मियों के लिए टर्म इंश्योरेंस उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब इसे 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

भारतीय सेना के कर्मियों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (पीएआई) की राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है। यह संशोधित सुविधा 14 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। भारतीय वायुसेना और सीआरपीएफ के कर्मियों को भी यह संशोधित सुविधा प्रदान की गई है, जो 4 फरवरी से प्रभावी हो गई है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (स्थायी पूर्ण विकलांगता) और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (स्थायी आंशिक विकलांगता) कवर की राशि में भी वृद्धि की गई है। पहले इन दोनों बीमा योजनाओं के तहत 50 लाख रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारतीय सेना में यह सुविधा 14 जनवरी से लागू हो गई है, जबकि वायुसेना और सीआरपीएफ में यह 4 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गई है।

हवाई दुर्घटना बीमा कवर (एएआई) की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह राशि एक करोड़ रुपये थी, जिसे अब डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारतीय सेना में यह संशोधित सुविधा 14 जनवरी से लागू हो गई है, जबकि वायुसेना और सीआरपीएफ में यह 4 फरवरी से प्रभावी हो गई है।

सीआरपीएफ कर्मियों के लिए टर्म इंश्योरेंस, जो पहले उपलब्ध नहीं था, अब 10 लाख रुपये का कर दिया गया है। यह सुविधा 24 फरवरी से प्रभावी हो गई है।

भारतीय सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ के पेंशनभोगियों के लिए भी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई) की राशि में वृद्धि की गई है। पहले भारतीय सेना के पेंशनरों के लिए यह राशि 30 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। यह संशोधित सुविधा 14 जनवरी से लागू हो गई है। इसी तरह, वायुसेना और सीआरपीएफ में भी पेंशनरों के लिए यह राशि 50 लाख रुपये कर दी गई है, जो 4 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गई है।

यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी की पीएचडी की फर्जी डिग्री से बने कई प्रोफेसर, जांच शुरू

शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्रियों के भी बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी से पीएचडी की फर्जी डिग्रियां जारी की गई थीं। इस मामले में अब जांच शुरू हो गई है। गौरतलब है कि इस फर्जी डिग्री मामले में यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और रजिस्ट्रार पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।

राजस्थान में जेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएड की फर्जी डिग्रियां पकड़े जाने के बाद अब आगरा में भी पीएचडी की फर्जी डिग्रियां मिलने का मामला सामने आया है। इससे जिला प्रशासन को यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई पीएचडी डिग्रियों की विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा है। इसी कारण इन डिग्रियों की जांच की तैयारी शुरू कर दी गई है।

फर्जी डिग्री मामले में यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉ. सुकेश यादव को एसओजी राजस्थान की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जबकि रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा को शिकोहाबाद से पकड़ा गया था। इन दोनों आरोपियों को जयपुर के दलाल अजय भारद्वाज के साथ जेल भेजा जा चुका है। अब फिरोजाबाद जिला प्रशासन भी शासन के निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी की भूमि, बिल्डिंग और विकास प्राधिकरण से संबंधित पूरे नक्शे की जांच कर रहा है।

इस बीच, आगरा एसटीएफ की टीम ने भी जेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी पीएचडी डिग्रियां बरामद की हैं। प्रशासन को शक है कि बड़े पैमाने पर पीएचडी की डिग्रियां वितरित की गई हैं। इसके अलावा, संदेह है कि यूनिवर्सिटी ने अन्य कोर्स जैसे पॉलीटेक्निक, बीटेक, डी–फार्मा, बीपीएड आदि की भी फर्जी डिग्रियां जारी की हैं।

भर्ती में भी गड़बड़ी की आशंका

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा चयन आयोग द्वारा निकाली गई 1600 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में भी यूनिवर्सिटी की फर्जी पीएचडी डिग्रियों का इस्तेमाल कर अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरियां हासिल की होंगी। इस मामले की जांच के लिए आगरा एसटीएफ की टीम सक्रिय हो गई है।

शिकोहाबाद और मैनपुरी से जुड़ सकते हैं तार

सूत्रों का कहना है कि न केवल असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती बल्कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर सरकारी नियमों की अनदेखी की गई है। बिजनौर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे कई बड़े शहरों में लोग फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इनका संबंध शिकोहाबाद और मैनपुरी के कुछ लोगों से होने की आशंका है। जांच टीम इस एंगल पर भी काम कर रही है। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि जेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी पीएचडी डिग्रियों का मामला संज्ञान में आया है। यूनिवर्सिटी पहले से बंद थी, लेकिन धीरे–धीरे अन्य विभागों से भी छात्र शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। कई अन्य कोर्स के छात्रों ने भी शिकायतें की हैं, जिसके बाद इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

यूनिवर्सिटी पहुंची एसटीएफ की टीम, दस्तावेज खंगाले

आगरा में फर्जी पीएचडी डिग्री पकड़े जाने के बाद एसटीएफ की टीम जेएस यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां उन्होंने पीएचडी और अन्य कोर्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद टीम आगरा लौट गई। दो दिन पहले, आगरा के शाहगंज इलाके में अजीतनगर मार्केट से आरोपी धनेश मिश्रा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से जेएस यूनिवर्सिटी समेत अन्य कई यूनिवर्सिटियों की फर्जी डिग्रियां मिलीं। वह ई–मेल के जरिए यूनिवर्सिटी से डिग्रियां मंगवाता था और फिर कोरियर के माध्यम से वितरित करता था। इस खुलासे के बाद एसटीएफ की टीम ने जेएस यूनिवर्सिटी का दौरा कर संबंधित अभिलेखों की जांच की। टीम अभी भी इस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

पार्किंसन

तेज गति से बढ़ रही है ये बीमारी, नहीं है इसका कोई भी इलाज

पार्किंसन रोग तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है, जो मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करती है, जहां से शरीर की गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं। इससे शरीर में कंपन, मांसपेशियों में जकड़न और गति धीमी हो जाती है। इसके कारण संतुलन बनाए रखने, चलने, खड़े होने, बोलने और बैठने में कठिनाई हो सकती है।

पिछले कुछ दशकों में दुनियाभर में कई तरह की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े हैं। हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की चर्चा हम अक्सर करते हैं, लेकिन क्या आप पार्किंसन रोग के बारे में जानते हैं? पिछले 10–15 वर्षों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि यह बीमारी वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है। यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जो व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। पार्किंसन रोग में शरीर के अंगों, विशेष रूप से हाथ–पैरों में कंपन होना आम है, जो लगातार बना रहता है और रोजमर्रा के कामों में बाधा डाल सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के बढ़ते खतरों को लेकर चेतावनी दी है। शोधकर्ताओं के अनुसार, अगर यह बीमारी इसी गति से फैलती रही, तो 2050 तक दुनियाभर में ढाई करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इस रोग का अब तक कोई निश्चित इलाज नहीं है।

पार्किंसन रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी

चीन की कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित अन्य शोधकर्ताओं ने हाल ही में चेतावनी दी है कि 2021 की तुलना में 2050 तक पार्किंसन रोगियों की संख्या में 112: की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब है कि 2050 तक दुनियाभर में ढाई करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। यह बीमारी उम्र बढ़ने के साथ अधिक आम होती जा रही है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, अकेले दक्षिण एशिया में अगले दो दशकों में अनुमानित रोगियों की संख्या 68 लाख तक पहुंच सकती है। भारत में भी इस बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, हर एक लाख लोगों में से 15 से 43 लोग इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं।

किन्हें अधिक खतरा होता है?

मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुरुषों में इस बीमारी का खतरा महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। 2021 में पुरुषों और

महिलाओं के बीच पार्किंसन रोग का अनुपात 1.46 था, जो 2050 तक बढ़कर 1.64 हो सकता है। यह आमतौर पर 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र में शुरू होता है, हालांकि कुछ दुर्लभ मामलों में यह युवा वयस्कों में भी देखा गया है। जिन लोगों के परिवार में पहले से यह बीमारी रही हो, उनमें आनुवंशिक रूप से इसके होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा, यदि आप किसी ऐसे कार्य में संलग्न हैं, जिसमें विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों या रसायनों के संपर्क में रहना पड़ता है, तो यह रोग होने का जोखिम और बढ़ सकता है।

पार्किंसन रोग क्या है?

पार्किंसन रोग तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है, जो मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करती है, जहां से शरीर की गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं। इससे शरीर में कंपन, मांसपेशियों में जकड़न और गति धीमी हो जाती है। इसके कारण संतुलन बनाए रखने, चलने, खड़े होने, बोलने और बैठने में कठिनाई हो सकती है। यहां तक कि हाथ–पैरों के लगातार हिलने के कारण भोजन करना भी मुश्किल हो सकता है।

शोधकर्ताओं ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 के आंकड़ों का विश्लेषण किया और 2022 से 2050 के बीच 195 देशों और क्षेत्रों में इस बीमारी के बढ़ने के कारणों की जांच की। उन्होंने पाया कि 90: नए मामलों का मुख्य कारण दुनिया की वृद्ध होती जनसंख्या है।

हाथों का कांपना सबसे आम लक्षण

पार्किंसन रोग के लक्षण व्यक्ति–व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। इसके शुरुआती लक्षण हल्के हो सकते हैं और लोगों को उनकी पहचान करने में समय लग सकता है। सबसे आम लक्षण हाथों या उंगलियों का लगातार कांपना है, जो कभी–कभी पैरों या जबड़े में भी हो सकता है। यहाँ तक कि जब आप आराम कर रहे होते हैं, तब भी हाथ हिलता रह सकता है। कुछ लोगों को बोलने में भी कठिनाई महसूस होती है।

अब भी नहीं है कोई इलाज

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पार्किंसन रोग का अभी तक कोई निश्चित इलाज नहीं है। हालांकि, कुछ दवाएं इसके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, और कुछ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। जीवनशैली में कुछ बदलाव इस बीमारी के लक्षणों को कम कर सकते हैं। फाइबर से भरपूर आहार और अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करने से कब्ज की समस्या को कम किया जा सकता है, जो पार्किंसन रोग में आम होती है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों की ताकत, चलने की क्षमता, लचीलापन और संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

नोटरू इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी बीमारी से जुड़ी अधिक जानकारी और सलाह के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

पार्किंसंस रोग के चरण

पार्किंसंस रोग के गंभीर प्रभाव होने में कई साल या कई दशक लग सकते हैं। 1967 में, दो विशेषज्ञों, मार्गरेट होहेन और मेल्विन याहर ने पार्किंसंस रोग के लिए स्टेजिंग सिस्टम बनाया।

आज, मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी–यूनिफाइड पार्किंसंस डिजीज रेटिंग स्केल (डबै–न्च्कै) इस बीमारी को वर्गीकृत करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मुख्य उपकरण है। डबै–न्च्कै चार अलग–अलग क्षेत्रों की जांच करता है कि पार्किंसंस रोग आपको कैसे प्रभावित करता है:

भाग 1– दैनिक जीवन के अनुभवों के गैर–मोटर पहलू । यह खंड मनोभ्रंश, अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक क्षमता– और मानसिक स्वास्थ्य–संबंधी मुद्दों जैसे गैर–मोटर (गैर–गतिशील) लक्षणों से संबंधित है। इसमें दर्द, कब्ज, असंयम, थकान आदि के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं।

भाग 2– दैनिक जीवन के अनुभवों के मोटर पहलू । यह खंड आंदोलन से संबंधित कार्यों और क्षमताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को कवर करता है। इसमें आपकी बोलने, खाने, चबाने और निगलने, कंपन होने पर खुद कपड़े पहनने और नहाने की क्षमता और बहुत कुछ शामिल है।

भाग 3– मोटर परीक्षण । एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पार्किंसंस रोग के आंदोलन–संबंधी प्रभावों को निर्धारित करने के लिए इस अनुभाग का उपयोग करता है। मानदंड आपके बोलने के तरीके, चेहरे के भाव, कठोरता और कठोरता, चलने की चाल और गति, संतुलन, गति, कंपन आदि के आधार पर प्रभावों को मापते हैं।

भाग 4– मोटर जटिलताएँ । इस खंड में एक प्रदाता यह निर्धारित करता है कि पार्किंसंस रोग के लक्षण आपके जीवन को कितना प्रभावित कर रहे हैं। इसमें यह भी शामिल है कि आपको हर दिन कितने समय तक कुछ लक्षण होते हैं, और क्या वे लक्षण आपके समय बिताने के तरीके को प्रभावित करते हैं या नहीं।

इस स्थिति का कारण क्या है?

हालाँकि पार्किंसंस रोग के लिए कई मान्यता प्राप्त जोखिम कारक हैं, जैसे कि कीटनाशकों के संपर्क में आना, अभी तक पार्किंसंस रोग के एकमात्र पुष्ट कारण आनुवंशिक हैं। जब पार्किंसंस रोग आनुवंशिक नहीं होता है, तो विशेषज्ञ इसे ष्इडियोपैथिकष् (यह शब्द ग्रीक से आया है और इसका अर्थ है अपनी खुद की बीमारी) के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

रोप-वे

से अब चंद मिनटों में पहुंच सकेंगें

केदारनाथ धाम

केदारनाथ यात्रा अब आसान और तेज होगी क्योंकि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक एक रोपवे बनाया जाएगा। इस रोपवे से 9 घंटे की चढ़ाई मात्र 36 मिनट में पूरी हो जाएगी।

अजय कुमार, लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे पर पहुंचकर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मॉ गंगा का मायका कहे जाने वाले उत्तरकाशी के मुखबा गांव में उनकी पूजा–अर्चना के साथ आरती की। यहां उनका पूजा अर्चना के साथ स्वागत किया गया। यहां के लोगों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री हर्षिल पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यहां आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर यहाँ आकर, आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं।

उधर, हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना भाषण गंगा मैया की जय से शुरू किया और गंगा मैया की जय पर ही खत्म किया. उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जनसभा में पहुंचे थे. प्रधानमंत्री मोदी जब हर्षिल और मुखबा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज गुरुवार को हर्षिल–मुखबा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उत्तरकाशी जिले के इस सीमावर्ती क्षेत्र में गजब का उत्साह और उल्लास देखने को मिला।

प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित कर कहा कि उत्तराखंड का हर्षिल–मुखबा आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चारधाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल है। आज एक बार फिर यहां आकर, आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिला।

सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच रोप-वे 12.9 किमी लंबा होगा, जिस पर 4081 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। हेमकुंड साहिब रोप-वे पर 2730 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब गुरुद्धारे तक की यात्रा को सुगम बनाएगा। यह प्रोजेक्ट चार से छह साल में पूरे हो जायेंगे।

मेरा मानना है कि उन्हीं की कृपा से मैं काशी पहुँचा और अब काशी के सांसद के रूप में सेवा कर रहा हूं।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा केंद्रीय कैबिनेट सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप–वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इससे तीर्थयात्री चढ़ाई से बच सकेंगे. सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच रोप–वे 12.9 किमी लंबा होगा, जिस पर 4081 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है. वहीं, हेमकुंड साहिब रोप–वे पर 2730 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक की यात्रा को सुगम बनाएगा. यह प्रोजेक्ट चार से छह साल में पूरे हो जायेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाली भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। और कहा, 'म्यारा प्यारा भाई भेणी, मेरी सयवा सोंदी'। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का बन रहा है। उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने यहां के शीतकालीन पर्यटन को प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि "घाम तापो पर्यटन" उत्तराखंड के लिए नया आयाम लेकर आएगा। मोदी ने कहा कि माणा, जादूंग, टिम्मरसैंण में तेजी से पर्यटन बढ़ रहा है। ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उत्तराखंड हर सीजन में ऑन सीजन रहेगा। मोदी ने लोगों से उत्तराखंड में आकर शादी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड को चुने। साथ ही उन्होंने फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड को बेहतर बताया।

मौजूदा समय केदारनाथ जाने का दो विकल्प हैं, पहला पैदल सात–आठ घंटे का सफर कर पहुंचा जा सकता है और दूसरा हेलीकॉप्टर सेवा है. हेलीकॉप्टर सेवा महंगी होने के साथ साथ अधिक मांग होने की वजह से असानी से उपलब्ध नहीं होता है. इस वजह से ज्यादा श्रद्धालु पैदल ही केदारनाथ पहुंचते हैं. वहीं, हेमकुंड साहिब तक का सफर पैदल करते हैं.

उत्तराखंड में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही मोदी ने कॉरपोरेट घरानों से आग्रह किया कि वह अपनी बैठकों के लिए उत्तराखंड आएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां विंटर योगा सेशन आयोजित किए जाएं।

प्रधानमंत्री ने धामी सरकार से कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए प्रतियोगिता आयोजित करें। वह उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म पर शॉर्ट फिल्म बनाएं। जो सबसे अच्छी बनाएं उन्हें इनाम दें। इससे प्रदेश के खूबसूरत स्थलों की जानकारी ज्यादा

अमेरिका में बंद होगा शिक्षा मंत्रालय, ट्रंप ने लिया फैसला

ट्रंप के इस फैसले की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका की शिक्षा प्रणाली को दुनिया की बेहतरीन व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। ऐसे में इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय के बंद होने के बाद अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान शिक्षा मंत्रालय को बंद करने के अपने वादे को पूरा किया है। उन्होंने इससे जुड़े एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अब संघीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय को समाप्त किया जाएगा।

ट्रंप के इस फैसले की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका की शिक्षा प्रणाली को दुनिया की बेहतरीन व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। ऐसे में इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय के बंद होने के बाद अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? इसका शिक्षण संस्थानों पर क्या असर होगा? उनके वित्तीय संसाधन कैसे प्रबंधित होंगे? छात्रों और उनके अभिभावकों की स्थिति क्या होगी? आइए जानते हैं...

अमेरिका में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना

अमेरिका में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और संघीय स्तर पर शैक्षिक नीतियों की निगरानी करना और स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

अमेरिका की शिक्षा प्रणाली भारत और अन्य देशों से अलग है। यहां शिक्षा की जिम्मेदारी संघीय सरकार की बजाय राज्य और जिला प्रशासन पर अधिक होती है। यानी संघीय शिक्षा मंत्रालय स्कूलों को संचालित करने या उनका

पाठ्यक्रम निर्धारित करने का कार्य नहीं करता, बल्कि यह जिम्मेदारी राज्यों और जिलों की होती है।

शिक्षा मंत्रालय की भूमिका

- संघीय शिक्षा मंत्रालय सरकारी और कुछ निजी स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा होता है, खासतौर पर दिव्यांग और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए।
- यह मंत्रालय अमेरिका में नागरिक अधिकारों को लागू करने में भी भूमिका निभाता है, ताकि स्कूलों में नस्लीय और लैंगिक भेदभाव न हो।
- शिक्षा मंत्रालय पूरे देश में स्कूलों के आंकड़े एकत्र करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का कार्य करता है।

हालांकि ट्रंप ने शिक्षा मंत्रालय को खत्म करने का आदेश दिया है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी। अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, मंत्रालयों की स्थापना, उनकी फंडिंग और अन्य प्रशासनिक अधिकार अमेरिकी संसद के अधीन होते हैं।

- अमेरिकी संसद के उच्च सदन (सीनेट) में ट्रंप को इस प्रस्ताव के लिए सुपरमेजोरिटी (100 में से 60 सांसदों का समर्थन) चाहिए होगा। वर्तमान में सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 53 और डेमोक्रेटिक पार्टी के 47 सदस्य हैं। ऐसे में ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के 7 सांसदों का समर्थन चाहिए, जो मुश्किल हो सकता है।
- निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में भी ट्रंप के लिए यह आसान नहीं होगा। इससे पहले जब शिक्षा मंत्रालय को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया था, तो रिपब्लिकन पार्टी के 60 सांसदों और पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसका विरोध किया था।

ट्रंप प्रशासन की आगे की योजना

इसके बावजूद ट्रंप अपने फैसले पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री लिंडा मैक्मेहन को आदेश दिया है कि वे इस मंत्रालय को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करें और संघीय जिम्मेदारियों को राज्यों और जिला प्रशासन को हस्तांतरित करें। हालांकि, इस आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय खत्म होने के बाद उसके कार्यक्रमों का क्या होगा या उसके कर्मचारियों को किसी अन्य मंत्रालय में स्थानांतरित किया जाएगा या नहीं। यह भी तय नहीं है कि संघीय सरकार शिक्षा से जुड़े वित्तीय सहायता और छात्रों के कर्ज की व्यवस्था कैसे करेगी। शिक्षा मंत्रालय को समाप्त करने से सैकड़ों स्कूलों को मिलने वाली वित्तीय सहायता बंद हो जाएगी। इसका असर शिक्षकों, छात्रों और खासकर दिव्यांग और अल्पसंख्यक छात्रों को बढ़ावा देने वाले स्कूलों पर अधिक पड़ेगा।

शिक्षा मंत्रालय का विरोध क्यों?

शिक्षा मंत्रालय की स्थापना के समय से ही रिपब्लिकन पार्टी इसके खिलाफ रही है। 1980 के राष्ट्रपति चुनाव में रोनाल्ड रीगन ने भी इसे खत्म करने की बात कही थी। रिपब्लिकन पार्टी का मानना है कि शिक्षा को राज्यों और स्थानीय प्रशासन के अधीन रखना चाहिए, ताकि वे अपनी जरूरत और आबादी के अनुसार निर्णय ले सकें। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ने शिक्षा मंत्रालय पर नागरिक अधिकारों के नाम पर उदारवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए वित्तीय सहायता की जगह कानूनी कार्रवाई करने का पक्ष लिया। ट्रंप प्रशासन ने कई कॉलेजों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के मामलों की जांच भी शुरू कर दी है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय को खत्म करने के उनके फैसले को लेकर आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आवास पर लगी आग में मिली भारी मात्रा में नगदी

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए जले हुए नोटों के फोटो और वीडियो

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब मिलने के बाद, देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की आंतरिक जांच के लिए शनिवार को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया और उन्हें न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया।

आग में जले नोटों के बंडल की तस्वीरें और वीडियो सामने आए

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग के दौरान जले हुए नोटों के बंडलों की तस्वीरें और वीडियो शनिवार को सार्वजनिक हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और फायर ब्रिगेड से प्राप्त साक्ष्यों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किया।

14 मार्च को जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास में आग लगने की घटना के बाद, वहां एक कमरे में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की खबर सामने आई। प्रारंभिक रिपोर्टों में इस नकदी की अनुमानित राशि 15 करोड़ रुपये बताई गई, हालांकि इस आंकड़े की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक

गुरुवार को, जस्टिस वर्मा के आवास से कथित रूप से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक आपात बैठक बुलाई। इसके तहत, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। यह रिपोर्ट 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जस्टिस वर्मा का तबादला उनकी मूल अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का निर्णय, उनके खिलाफ लगे आरोपों से अलग था।

पहले भी आ चुका है जस्टिस वर्मा का नाम

इसके अलावा, यह जानकारी भी सामने आई कि फरवरी 2018 में

आग में जले नोटों के बंडल की तस्वीरें और वीडियो सामने आए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग के दौरान जले हुए नोटों के बंडलों की तस्वीरें और वीडियो शनिवार को सार्वजनिक हो गए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (ब्ठप्) ने जस्टिस वर्मा को सिंभावली चीनी मिल घोटाले में आरोपी के रूप में नामित किया था। इस मामले में 97.85 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की कथित हेराफेरी हुई थी। उस समय, जस्टिस वर्मा कंपनी के गैर–कार्यकारी निदेशक थे। हालांकि, सीबीआई की प्रारंभिक जांच के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की फिर से जांच के एक अदालती आदेश को रद्द कर दिया, जिससे यह मामला प्रभावी रूप से समाप्त हो गया।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू
- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया
- कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन

प्रधान न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा से निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा:

- आपके बंगले में स्थित कमरे में मिली नकदी के बारे में आपका क्या कहना है?
- इस नकदी का स्रोत स्पष्ट करें।
- 15 मार्च की सुबह, उस कमरे से जले हुए नोटों को किसने हटाया?

जस्टिस वर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा:

- मुझे या मेरे परिवार को स्टोर रूम में रखी नकदी की कोई जानकारी नहीं है।
- जब हमें नकदी के बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो उसके स्रोत पर कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता।
- 15 मार्च को मेरे परिवार ने घटनास्थल पर कोई जले हुए नोट नहीं देखे।
- 15 मार्च को कमरे से जले नोटों के बंडल या कबाड़ हटाने की खबर पूरी तरह गलत है, क्योंकि वहां का मलबा अभी भी यथावत है।
- स्टोर रूम बंगले के बाहरी हिस्से में स्थित था और लिविंग एरिया से पूरी तरह अलग था। यह केवल कबाड़ रखने के लिए उपयोग किया जाता था। इसका ताला बंद नहीं रहता था और वहां गार्ड, नौकर तथा बाहरी कर्मचारी आते–जाते थे।
- मुझे बदनाम करने और फंसाने की साजिश रची जा रही है, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को घटना की तस्वीरें और वीडियो उपलब्ध कराए। पुलिस के अनुसार, जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से सुबह कुछ मलबा और आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थीं। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्रथम दृष्टया यह मामला गहन जांच की मांग करता है।

पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट

- आग 30, तुगलक क्रीसेंट बंगले में लगी, जो जस्टिस वर्मा को आवंटित था।
- यह आग चारदीवारी से सटे स्टोर रूम में लगी थी।
- आग पर दो दमकल गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया।
- मौके पर चार से पांच अधजली बोरियां मिलीं, जिनमें भारतीय मुद्रा के जले हुए अवशेष मौजूद थे।

जस्टिस वर्मा को दी गई हिदायत

- अपने मोबाइल फोन को नष्ट न करें।
- मोबाइल में किसी भी संदेश, डेटा या बातचीत को न हटाएं।
- किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ न करें।

14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के बंगले में आग लगने के बाद15 मार्च को नोटों के जलने की जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी गई। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक हुई और 21 मार्च को मीडिया में इस खबर के आने के बाद तेजी से कार्रवाई शुरू हुई। 21 मार्च को सीजेआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी और 22 मार्च की दोपहर तक जस्टिस वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया। उसी दिन शाम को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया।

संकट में पाकिस्तान
अंदर-बाहर हर तरफ हाहाकार

पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी कम खराब नहीं है। एक तरफ पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, सिंध प्रांत की जनता पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जहर उगल रही है, वहीं ब्लूचिस्तान प्रांत की विद्रोही जनता तो पाकिस्तान की अखंडता के लिये ही खतरा बन गया है। यहां के लोग पाकिस्तान से अलग पूर्ण आजादी चाहते हैं।

संजय सक्सेना, लखनऊ

पड़ोसी देश पाकिस्तान चौतरफा मुसीबतों से घिरता जा रहा है। चीन की दोस्ती उसे डूबों रही है तो भारत और अफगानिस्तान से दुश्मनी उसे भारी पड़ रही है। अमेरिका में भी ट्रम्प सरकार आने के बाद वहां से पाकिस्तान पर मेहरबानियों का सिलसिला थम गया है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी कम खराब नहीं है। एक तरफ पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, सिंध प्रांत की जनता पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जहर उगल रही है, वहीं ब्लूचिस्तान प्रांत की विद्रोही जनता तो पाकिस्तान की अखंडता के लिये ही खतरा बन गया है। यहां के लोग पाकिस्तान से अलग पूर्ण आजादी चाहते हैं। इसके चलते बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान सेना के बीच लगातार संघर्ष होता रहता है। हद तो तब हो गई जब 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया, जिसमें लगभग 440 यात्री सवार थे। इस हमले में बीएलए ने ट्रेन को रोककर यात्रियों को बंधक बना लिया और सुरक्षाबलों पर हमला किया, जिससे 21 यात्रियों और 4 अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 33 आतंकवादियों को मार गिराया और बचे हुए यात्रियों को सुरक्षित छुड़ा लिया।

इस घटना के बाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक राजनीतिक संकल्प और बेहतर शासन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया, हालांकि उन्होंने इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया। भारत ने इन आरोपों को खारिज

किया है।

ट्रेन हाईजैक के बाद, बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के नोशकी इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर एक और बड़ा हमला किया, जिसमें कई सैनिक हताहत हुए। यह घटना बलूच विद्रोहियों की बढ़ती गतिविधियों को दर्शाती है, जो बलूचिस्तान में अधिक स्वायत्तता और संसाधनों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।

इन घटनाओं के मद्देनजर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने देश को सख्त राष्ट्र बनाने और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बेहतर शासन और राजनीतिक संकल्प की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 18 मार्च, 2025 को अपने एक बयान में पाकिस्तान को एक कठोर राज्य में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष देश के अस्तित्व के लिए एक लड़ाई है। जनरल मुनीर ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक में की, जो बलूच आतंकवादियों द्वारा एक यात्री ट्रेन का अपहरण करने के कुछ दिनों बाद बुलाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 25 यात्रियों की मौत हो गई थी।

मुनीर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष "हमारे और हमारी भावी पीढ़ियों के अस्तित्व की लड़ाई है।" उन्होंने बेहतर शासन और पाकिस्तान को एक "कठोर राज्य" बनाने का आह्वान किया और पूछा, "हम कब तक एक नरम राज्य की शैली में अनगिनत लोगों की जान कुर्बान करते रहेंगे?" जनरल मुनीर ने कहा, "स्थायी विकास के लिए, राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों को सामंजस्य के साथ काम करना होगा।"

बात बलूचिस्तान, के भौगोलिक और राजनैतिक परिदृश्य की कि जाये तो यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, लंबे समय से देश के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। यहां के अलगाववादी आंदोलन, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मांग, और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप पाकिस्तान की स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं। दरअसल, 1947 में भारत से अलग मुसलमानों के लिये पाकिस्तान देश बनने के बाद, बलूचिस्तान के कलात राज्य ने पाकिस्तान में विलय से इंकार कर दिया था। हालांकि, 1948 में पाकिस्तानी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया, जिससे बलूच राष्ट्रवादियों में असंतोष बढ़ा। तब से, बलूचिस्तान में कई बार विद्रोह हुए हैं, जिनमें 1950, 1960, 1970 और 2000 के दशक शामिल हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, बलूच अलगाववादी समूहों की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2015 से 2024 के बीच, इन समूहों द्वारा किए गए हमलों की संख्या चार गुना बढ़कर 171 हो गई है। इन हमलों में लगभग 590 लोग मारे गए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल हैं।

गौरतलब हो बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें गैस, सोना, और तांबा शामिल हैं। हालांकि, स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इन संसाधनों का लाभ उन्हें नहीं मिलता, बल्कि पाकिस्तान के अन्य प्रांतों को मिलता है। यह आर्थिक असंतोष अलगाववादी

भावनाओं को बढ़ावा देता है। ब्लूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान सेना की हैवानियत का भी शिकार होता रहा है। बलूच कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों के जबरन गायब होने की घटनाएं बलूचिस्तान में आम हैं। वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स (वीबीएमपी) के अनुसार, बलूचिस्तान से 7,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। हालांकि, सरकारी आंकड़े इससे कम हैं, लेकिन यह मुद्दा स्थानीय निवासियों में गहरा असंतोष पैदा करता है।

बलूचिस्तान में यहां के निवासियों के भारी विरोध के बाद भी चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) और अन्य विदेशी निवेश परियोजनाएं चल रही हैं,जबकि अलगाववादी समूह इन परियोजनाओं को अपने संसाधनों के शोषण के रूप में देखते हैं और इन्हें निशाना बनाते हैं। अगस्त 2024 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने एक घातक हमला किया, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। फरवरी 2025 में कलात जिले में एक बड़े संघर्ष में 18 पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों और 23 विद्रोहियों मतलब बीएलए के सदस्यों की मौत हुई थी।

बलूचिस्तान में जारी संघर्ष पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर खतरा पैदा कर रहा है। लगातार हमलों से पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ता है और देश की आंतरिक स्थिरता खतरे में पड़ती है। सीपीसीई जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं

चीनी ने पाकिस्तान को लोन देकर अपने चंगुल में फंसा लिया है। पाकिस्तान ने चीन से सबसे अधिक लोन दिया है। यह लोन लगभग 28.6 बिलियन डॉलर है, जो उसके कुल कर्ज का 22 प्रतिशत है। विश्व बैंक के अनुसार, देश पर कुल मिलाकर लगभग 130 अरब डॉलर का कर्ज है। आज पाकिस्तान की हालत बेहद खस्ता है। यहां तक कि वहां पर आटे–दाल–चावल, सब्जियां और दूध तक आम आदमी की पहुंच से दूर जा चुके हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है।

पर हमलों से विदेशी निवेशकों का विश्वास कम होता है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। वहीं मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि धूमिल होती है, जिससे कूटनीतिक संबंध प्रभावित होते हैं।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची तलवारें

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनाव की वजह पर नजर दौड़ाई जाये तो दोनों देशों के बीच डुरंड रेखा विवाद का बड़ा कारण है। 1893 में ब्रिटिश शासन द्वारा खींची गई डुरंड रेखा को अफगानिस्तान ने कभी मान्यता नहीं दी है। यह सीमा विवाद दोनों देशों के बीच तनाव का एक ऐतिहासिक स्रोत है। उधर, पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन से संचालित होकर पाकिस्तान में आतंकी हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन तालिबान ने इसे अस्वीकार कर दिया है। हाल ही में, तोरखम सीमा चौकी पर पाकिस्तानी और अफगान सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं, जिससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत और कई घायल हुए हैं। यह संघर्ष सीमा पर एक नए चौकी के निर्माण को लेकर हुआ, जिससे तनाव और बढ़ गया है। दिसंबर 2024 में, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई। अफगान रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया।

चीन के चंगुल में फंसता पाकिस्तान

चीनी ने पाकिस्तान को लोन देकर अपने चंगुल में फंसा लिया है। पाकिस्तान ने चीन से सबसे अधिक लोन दिया है। यह लोन लगभग 28.6 बिलियन डॉलर है, जो उसके कुल कर्ज का 22 प्रतिशत है। विश्व बैंक के अनुसार, देश पर कुल मिलाकर लगभग 130 अरब डॉलर का कर्ज है। आज पाकिस्तान की हालत बेहद खस्ता है। यहां तक कि वहां पर आटे–दाल–चावल, सब्जियां और दूध तक आम आदमी की पहुंच से दूर जा चुके हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है। पाकिस्तान ने अपनी नाजुक वित्तीय स्थिति के चलते आईएमएफ से आपातकालीन फंड मांगता रहा है। हालांकि, चीन के लिए पाकिस्तान चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का घर है। यह चीन के पश्चिमी प्रांतों को बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाला लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा गलियारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कर्ज देकर वहां अपना आधिपत्य बनाता जा रहा है।

अब अगले 11 साल तक सर्दियों में पड़ेगा रमजान का पाक महीना

रमजान का पाक महीना अब अगले 11 साल तक सर्दियों में आएगा। 2007 से 2025 तक रोजे गर्मियों के मौसम में रखे गए थे। लेकिन 2026 से 2036 तक रोजेदारों को तेज धूप और गर्मी से राहत मिलेगी।

जैसे ही रमजान का महीना पूरा होने वाला है, वैसे ही गर्मी में रोजेदारों की परीक्षा भी समाप्त हो जाएगी। 2007 से 2025 तक 19 वर्षों तक रोजेदारों ने चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच इबादत की। लेकिन अब अगले 11 वर्षों तक रमजान सर्दियों के बीच ही गुजरेगा। 2026 से 2036 तक रमजान का आगमन ठंडे मौसम में होगा। वर्ष 2007 से 2025 तक 19 बार रमजान आया, और इस्लामिक कैलेंडर का यह पाक महीना मार्च से सितंबर के बीच पड़ता रहा। इस दौरान कभी अप्रैल–मई की तपिश रही, तो कभी जून–जुलाई–अगस्त की उमस भरी गर्मी ने रोजेदारों को आजमाया। मार्च और सितंबर महीने भी इसमें शामिल रहे। इन वर्षों में मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त में तीन–तीन बार रमजान आया, जबकि जून और सितंबर में दो–दो बार इसकी शुरुआत हुई।

रमजान का महीना अब धीरे–धीरे सर्दियों की ओर बढ़ रहा है। आने वाले 11 साल रोजेदारों के लिए राहत भरे होंगे, क्योंकि 2026 से 2036 तक रमजान ठंडे मौसम में आएगा। इस दौरान दिसंबर, जनवरी और फरवरी की कड़ाके की ठंड में रोजे रखे जाएंगे। इसके अलावा, अक्टूबर और नवंबर की हल्की ठंड भी रोजेदारों के लिए आरामदायक होगी।

हर साल 10 से 12 दिन पीछे खिसकता है रमजान

मदरसा अरबिया इमदादिया के मोहतमिम और शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद असजद कासमी के अनुसार, रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है, जिसकी तारीखें हिजरी चंद्र कैलेंडर के अनुसार तय होती हैं। इस कैलेंडर में 12 चंद्र महीने होते हैं, और हर महीना अर्द्धचंद्र के दिखाई देने से शुरू होता है। चंद्र महीना 29 या 30 दिनों का होता है, जिससे चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। इसी कारण ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में यह हर साल 10 से 12 दिन पहले आ जाता है और हर 33 वर्षों में एक बार पूरा मौसमी चक्र पूरा करता है।

2030 में दो बार आएगा रमजान

वर्ष 2030 मुसलमानों के लिए खास होगा, क्योंकि इस साल रमजान दो बार आएगा। एक बार साल की शुरुआत में और दूसरी बार साल के अंत में। यानी वर्ष 2030 में जनवरी और दिसंबर दोनों महीनों में रमजान का आगमन होगा।

2033 में दो बार मनाई जाएगी ईद

वर्ष 2030 में रमजान दो बार आने के बाद, 2033 में मुसलमानों को दो बार ईद मनाने का अवसर मिलेगा। पहली ईद जनवरी में और दूसरी दिसंबर में होगी, जिससे यह साल भी खास बन जाएगा।

पंजाब में किसान आंदोलन पर कड़ा एक्शन, आप सरकार ने बदला रुख

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, जो अब तक किसानों के समर्थन का दावा करती रही थी, अचानक ही उनके खिलाफ नजर आ रही है। इसका असर यह हुआ कि न केवल किसान, बल्कि विपक्षी दल भी भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पंजाब सरकार ने अचानक किसानों के मामले में यू-टर्न क्यों लिया?

अजय कुमार, लखनऊ

पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर लगातार बदलते घटनाक्रम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुई पुलिस की कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन से किसान संगठनों में गहरा असंतोष फैल गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, जो अब तक किसानों के समर्थन का दावा करती रही थी, अचानक ही उनके खिलाफ नजर आ रही है। इसका असर यह हुआ कि न केवल किसान, बल्कि विपक्षी दल भी भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पंजाब सरकार ने अचानक किसानों के मामले में यू-टर्न क्यों लिया?

लंबे समय से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को हिरासत में ले लिया। उनके साथ-साथ किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख सरवन सिंह पंढेर और आंदोलन में शामिल अन्य किसानों को भी मोहाली में हिरासत में लिया गया। ये सभी किसान नेता चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करके लौट रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने देर रात शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया। आंदोलनरत किसानों के स्थायी और अस्थायी ढांचों को भी बुलडोजर से हटा दिया गया। पंजाब सरकार के इस कड़े रुख ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसानों के समर्थन में खड़ी रही है।

भगवंत मान का बदला हुआ रुख हैरान करने वाला है। शुरुआत में पंजाब सरकार ने कोर्ट में किसानों के पक्ष में दलील दी थी कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो इससे देशभर में अशांति फैल सकती है। इसके बावजूद सरकार ने किसान नेताओं के साथ बातचीत जारी रखी, कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर कमेटी भी बनाई, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकला। किसानों का विरोध लगातार जारी रहा, खासकर जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया था। 10 जुलाई 2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोला जाए।

हरियाणा सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन अब पंजाब सरकार ने खुद ही बॉर्डर को खाली करा दिया है। यह फैसला इसलिए चौंकाने वाला है, क्योंकि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था और उनके साथ खड़े रहने का वादा किया था। किसानों के समर्थन के चलते आम आदमी पार्टी को पंजाब में सत्ता भी मिली थी।

शुरुआती दौर में पंजाब सरकार किसान आंदोलनकारियों का समर्थन करती दिखी और केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही, लेकिन अब उसी पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर दी है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मामले पर कहा

कि सरकार शंभू और खनौरी बॉर्डर को खोलना चाहती है, ताकि राज्य में सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे। उनका यह भी कहना था कि किसानों को विरोध–प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं।

किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों से निजी खुन्नस हो सकती है, जिसकी वजह से यह कार्रवाई हुई है। मार्च की शुरुआत में पंजाब सरकार और किसान नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका।

किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका विरोध किया। बैठक के दौरान किसानों और मुख्यमंत्री के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद भगवंत मान ने गुस्से में बैठक छोड़ दी और कहा कि अब कुछ नहीं होगा। इसके तुरंत बाद पंजाब पुलिस ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।

इसके अगले ही दिन भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने बैठक छोड़ी थी और सरकार किसानों को हिरासत में लेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसानों को रेलवे ट्रैक और सड़कों पर धरना देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद पुलिस ने कई किसान नेताओं को उनके गांवों में ही रोक लिया। बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर उगराहां समेत कई बड़े किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस ने बॉर्डर पर भी कड़ा एक्शन लिया। इस पूरे घटनाक्रम से यह समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या यह कार्रवाई केवल भगवंत मान की नाराजगी के कारण हुई या फिर इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का भी कोई निर्देश था।

अगर पंजाब सरकार को यह पता था कि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं, तो यह कार्रवाई पहले ही क्यों नहीं हुई? अगर सरकार पहले ही कदम उठा लेती, तो यह विवाद इतना बड़ा नहीं बनता। इससे आम आदमी पार्टी और भगवंत मान विपक्षी दलों के निशाने पर आने से बच सकते थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब सरकार इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रही है। पहले भी ऐसा देखा गया था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर भेज दिया था और केंद्र सरकार को ही इसका समाधान निकालने के लिए मजबूर कर दिया था। तब केंद्र सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। लेकिन इस बार मामला उल्टा नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवंत मान और उनकी सरकार खुद ही इस विवाद को अपने सिर ले रही है।

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी हो रही है कि किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की एक वजह लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर संभावित उपचुनाव भी हो सकता है। खबरों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को लुधियाना के व्यापारियों से यह फीडबैक मिला था कि अगर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा, तो वे आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा था। इसी कारण पंजाब सरकार ने बॉर्डर खाली कराने का फैसला लिया। हालांकि, यह उपचुनाव अभी कब होगा, इसका भी कोई ठोस संकेत नहीं मिला है।

ऐसी भी संभावना थी कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ–साथ लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव हो सकता है। अगर ऐसा होता, तो आम आदमी पार्टी किसानों से बातचीत कर इस मामले का शांतिपूर्ण हल निकाल सकती थी। लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जिससे मामला और बिगड़ गया।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी है। ऐसे में कुछ लोग मान रहे हैं कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भी यह कार्रवाई हो सकती है।

पंजाब सरकार की इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। 2022 में किसानों के समर्थन के दम पर सत्ता में आई यह पार्टी अब उन्हीं किसानों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। ऐसे में किसान संगठनों की नाराजगी भविष्य में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, भगवंत मान सरकार ने इस मामले में जो जल्दबाजी दिखाई, वह नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर सरकार इस मसले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर हल करने देती, तो पंजाब सरकार पर कोई दोष नहीं आता। लेकिन अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसानों के खिलाफ इतना सख्त एक्शन क्यों लिया गया। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि मामला पूरी तरह से राजनीतिक है और इसके पीछे कोई न कोई रणनीति जरूर है।

टैटू से कैंसर होने का खतरा: नई रिसर्च का खुलासा

लंबे समय से टैटू और कैंसर के बीच संबंध को लेकर चर्चा हो रही है। हाल ही में एक नई स्टडी में इसका खुलासा हुआ है, जो रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुई है।

इस शोध में पाया गया है कि जितना बड़ा टैटू होगा, कैंसर होने का खतरा उतना ही अधिक होगा। अगर आप टैटू के शौकीन हैं, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है।

टैटू से किस प्रकार के कैंसर का खतरा?

बीएमसी पब्लिक हेल्थ रिसर्च के अनुसार, करीब 2 हजार लोगों पर एक तुलनात्मक स्टडी की गई। इसमें टैटू वाले और बिना टैटू वाले लोगों के सैंपल का अध्ययन किया गया। शोध में पाया गया कि टैटू कराने वालों में दो प्रकार के कैंसर का जोखिम अधिक होता है:

- स्किन कैंसर: 137 प्रतिशत अधिक
- ब्लड कैंसर (लिंफोमा): 173 प्रतिशत अधिक

टैटू इंक से कैंसर का कारण

अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी के अनुसार, टैटू के काले इंक में मौजूद कार्बन ब्लैक और रंगीन इंक में मौजूद एजो कंपाउंड्स कैंसर का कारण बन सकते हैं। खासकर, सूर्य के प्रकाश या लेजर ट्रीटमेंट के संपर्क में आने पर ये कंपाउंड्स कैंसरजन्य हो सकते हैं।

टैटू की स्याही का शरीर में फैलना

शोधकर्ताओं का मानना है कि टैटू की स्याही के कण शरीर में फैलकर लसीका ग्रंथियों में जमा हो सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

टैटू बनवाते समय ध्यान रखने योग्य बातें

- टैटू छोटा और सादा बनवाएं।
- डार्क और रंगीन इंक से बचें।
- अच्छी गुणवत्ता वाली नीडल और स्याही का ही उपयोग करें।
- अनुभवी टैटू आर्टिस्ट से ही टैटू बनवाएं।
- टैटू पार्लर को अच्छी तरह जांच परख लें।
- टैटू बनवाने से पहले और बाद में त्वचा की जांच कराएं।

विश्व में टैटू का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में इसका मूल्यांकन 2.22 मिलियन डॉलर है और 2032 तक यह 4.83 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। टैटू बनवाने का ट्रेंड भी 20–25 प्रतिशत बढ़ा है। टैटू बनवाने से पहले इसके स्वास्थ्य प्रभावों को समझना बेहद जरूरी है। जागरूकता और सावधानी से ही हम कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं।

मेरा पन्ना

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

परीक्षा

आई परीक्षा आई परीक्षा
हाय परीक्षा हाय परीक्षा
देख गणित को चक्कर आता
अंग्रेजी से मन घबराता
भूल-भुलैया हिन्दी की बिंदी
संस्कृत हो या, या हो सिंधी
याद नहीं होता भूगोल
इतिहास में भी डिब्बा गोल
अम्ल क्षार सा लगे विज्ञान
प्रभु हमारा रखना ध्यान
अपने पर रखो विश्वास
मेहनत से तुम होगे पास
नही परीक्षा भूत है भैया
काहे करते ता ता थैया।

आर.एन.आई. नं.- RAJHIN/2019/77486

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

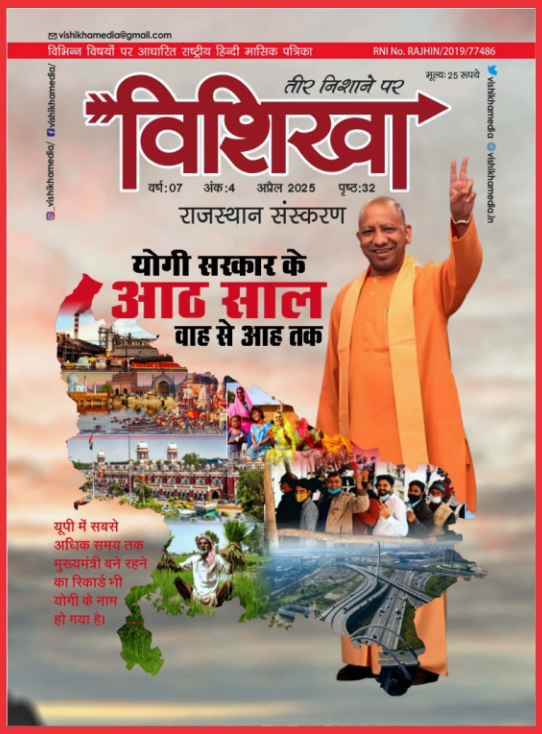

राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद विशिखा

अब शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित...

विशिखा
तीन निशाने पर

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर-302033 (राज.)
Contactus:+911413562171,9587455444
E-mail:vishikhamedia@gmail.com | Website:www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia